

of research on the wheat crop under the overall coordination of the Indian Council of Agricultural Research. India has probably the largest number of scientists and institutions engaged in different aspects of wheat research in the world. The all-India Coordinated Wheat Improvement Project has as many as 30 centres and a large number of sub-centres located in different parts of the country, including the Agricultural Universities and the Central Institutes. These research centres have been integrated in their programmes through the mechanism of the all-India Coordinated Wheat Improvement Project which has become a model for organization of research and has received appreciative comments from several developing countries as well as international organizations.

(b) India's wheat production technology is considered to be one of the finest in the world. The country has a very large number of improved varieties having a yield potential of nearly 6-7 tonnes per hectare which compares favourably with some of the highest reported yields of wheat in the world for a maturity duration of 140 to 150 days. Many of the new wheat varieties are also notable for their high degree of disease resistance specially the three rusts. Last year, India supplied to Pakistan large quantities of seeds of some of these varieties on a request from that country. These varieties have helped the country to sustain the production advance in wheat. The Indian wheat scientists in more recent years have paid considerable attention to the developing of multiline varieties, which combine in them disease resistance from several different sources. India is the first country in the world to release multiline varieties of dwarf wheat. The major emphasis in India's wheat Improvement Programme has been on high levels of yield and here the country occupies a very favourable position on a world-wide basis. Our scientists are also now

paying serious attention to the quantity attributes of the new wheat varieties.

(c) Yes, Sir.

शरीक की फसल के लिए बीज तथा उर्वरक

8957. श्री राजेश कुमार शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार धायानी शरीक की फसल के लिए किसानों को बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध कराने हेतु सुविधायें जुटाने के लिये कोई कार्यक्रम बना रही है ताकि किसानों को समय पर सही सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार किन ऐजेंसियों के माध्यम से इन सुविधाओं को किसानों को उपलब्ध करायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) यह उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है कि बीजों व उर्वरकों आदि के वितरण का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। तथापि भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता देती है कि वे मई कृषकों को समय पर उपलब्ध हो सकें। शरीक के बालू मौसम के लिये जिस तरीके से यह कार्य किया गया उस का अ्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) बीज :—भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे इस बात का पता लगायें कि क्या शरीक 1979 के लिये बीजों की किसी प्रकार की कमी थी ताकि उन्हें उन स्रोतों से भवगत कराया जा सके जिस से कमी की पूर्ति हो सकती है। अभी तक किसी भी राज्य से कमी होने की सूचना नहीं मिली है। राष्ट्रीय बीज निगम को निर्देश दे दिया गया है कि वह राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये रखे तथा किसी प्रकार से कमी होने पर उन की मदद करे।

(2) उर्वरक :—शरीक 1979 के लिये प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र जिस बोर्ड की उर्वरकों की प्राथमिकताएँ मौसम के आरम्भ होने से पहले क्षेत्रीय सम्मेलनों में निश्चित की गई थी। बरेलू निर्माताओं तथा आयात से उर्वरकों की आपूर्ति की एक सम्बन्धित योजना उसी समय तैयार की गई थी ताकि उक्त प्राथमिकताओं की पूर्णतः पूर्ति की जा सके। राज्य सरकार के अधिकारियों, देशी निर्माताओं तथा एजेंसियों (जो आयातित उर्वरकों का संचालन करते हैं) के साथ सप्ताह की निश्चित का पूर्वाभिकार करने के लिए समय समय पर बैठकें हुई हैं, ताकि कमी का पता लगाया जा सके और प्राथमिकता पकने पर उपयुक्त उपाय किये जाएँ।

(3) कीटनाशी दवाओं की तरह कीटनाशी दवाओं की राज्यवार/क्षेत्रवार आवश्यकताएँ खेती का मौसम शुरू होने से पहले हुई कीर्तवीर सम्मेलन की बैठक में तथा राज्य सरकारों और वेकी उपयोग के साथ प्रचलित भारतीय वनस्पति रक्षण संबंधी वार्षिक सम्मेलनों में निश्चित की गई थी, इससे इस बात की सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि राज्य सरकारों को कीटनाशी दवाओं की संभावित उपलब्धि की जानकारी मिल सके तथा उद्योग को अपनी भांग का पता चल सके ताकि भांग के अनुसार उत्पादन किया जा सके। कमी होने की स्थिति में उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके आयात करने की योजना बनाई जाती है।

विभागीय विक्रय डिप्युमें, सहकारी विपणन संघों, कृषि उद्योग सहकारिताएँ, पंचायतें आदि अपने-अपने-अपने कीटनाशी दवाओं का बितरण करती हैं। व्यापारियों ने देश के विभिन्न भागों में अपने उत्पादक कृषकों को सीधा बेचने के लिए विक्रय केंद्रों का एक जाल बिछाया हुआ है।

हाथ से संचालित होने वाले टेलीफोन केंद्रों वाले स्थान पर कालों में विलम्ब होना

9958. श्री राजेश कुमार शर्मा: क्या संचार पंजी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिन स्थानों में हाथ से संचालित होने वाले टेलीफोन केंद्र हैं वहाँ टेलीफोन उपभोक्ताओं को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब भी उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मरहूर प्रसाद मुजुबेब साह): (क) हाथ से संचालित होने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में उपभोक्ताओं को कभी कभी कनेक्शन जोड़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव हो रहा है।

(ख) मुख्य कारण है:—

(i) आपरेटरो द्वारा जवाब देने में विलंब।

(ii) कुछ खास मौकों पर उपस्कर का लुटि-पूर्ण संचलन।

(ग) (i) प्रचालक कर्मचारियों द्वारा तुरंत जवाब दिया जाय, इसे सुनिश्चित करने के लिए बेहतर पर्यवेक्षण।

(ii) प्रतिघोष दोष निवारण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और सक्षम कर्मचारियों का तैयार किया जाना।

(iii) हस्ताक्षरित एक्सचेंजों की उत्तरोत्तर स्थापित एक्सचेंजों में बदलाव जा रहा है।

Pay scales of Junior Engineers in Telecom. Wing

9959. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Junior Engineers in the Telecom. Wing are now being paid less pay than their subordinates in the cadre of SG AEA/SGRSASGPI/SGWO etc.;

(b) whether it is a fact that the revision of pay scale of the SG AEA/SGRSA/SGPI/SGWO etc. had resulted them in drawing less pay on promotion to the cadre SG AEA/SGRSA/SGPI/SGWO etc.; and

(c) if so, what action has been taken to revise the pay scale of the Junior Engineers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) No, Sir. However, the pay scales of both the cadres are as below:—

	O.G.	S.G.
J.Ex.	425—700	550—900
SGRSA etc.	..	425—700 (Revised from 425— 640 w.e.f. 29-5-78)

(b) No, Sir.

(c) In view of (a) and (b) above the question does not arise.

D.D.A. flats for Members of Parliament

9960. SHRI ISHWAR CHAUDHRY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of Members of Parliament who have got themselves registered with Delhi Development Authority for the purchase of flats when; and

(b) whether they have been allotted flats so far?